बिजली, पेय जल और शौचालयों की सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या अनुमान है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त प्रतिशतता में वृद्धि करने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर०के० धवन): (क) और (ख) ऐसा अनुमान है कि 31.12.1991 तक 85.31% शहरी आबादी को पेयजल आपूर्ति तथा 46.64% आबादी को सफाई सुविधा मुहैया करायी जा चुकी है। जहां तक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का सवाल है, 31.3.1994 तक शहरी उपभोक्ताओं सहित देश में कुल संख्या 6,01,93,172 थी।

(ग) और (घ) उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति, सफाई तथा घरेलू बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकारों/संबंधित स्थानीय निकायों का दायित्व है। सदी के अन्त तक, शत-प्रतिशत शहरी आबादी को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति पहुंचाने का प्रस्ताव है। 20,000 तक की आबादी वाले शहरों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष बल देते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 की भागीदारी में केन्द्र प्रवर्तित त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 132 शहरों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं पहले ही मंजूर कर दी गई हैं।

आठवीं योजना में कम लागत की केन्द्र प्रवर्तित स्कीमों के जरिए शहरी क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जल-वाही शौचालयों में बदलने का विचार है। इस स्कीम में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 45% सब्सिडी, 50% राज्य धन/कर्ज व 5% लाभार्थी अंशदान का प्रावधान है।

बिजली आपूर्ति बढ़ाने हेतु बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिसमें नई विद्युत उत्पादन यूनिटें शीघ्र बनाकर चालू करने, काम विवाद में फलदायी परियोजनाएं चलाने, मौजूदा बिजली घरों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने, विद्युत पारेषण व वितरण में छीज[illegible] कम करने, बेहतर मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण [illegible] लाने, आधिक्य क्षेत्रों से अभाव क्षेत्रों को ऊर्जा के अंतरण तथा निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना आदि का समावेश है।

पंजाब में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले

1773. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो वहां औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में कितने जिलों की पहचान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार पंजाब के पिछड़े जिलों के तीव्र गति से विकास हेतु क्या आवश्यक उपाय कर रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) से (घ) सरकार, देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची तैयार कर रही है। देश में औद्योगिक विकास के बारे में स्थानीय असन्तुलनों को कम करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 71 विकास केन्द्र और 50 एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों के स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु कर प्रोत्साहन देने के लिये आयकर अधिनियम में भी प्रावधान किया गया है।

Freeze Order on construction in New Delhi

1774. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the building being constructed at 5, Dr. Rajendra Prasad Road is in contravention of the freeze order issued by the Prime Minister saying that no building should be constructed or changed in the Lutyen's, New Delhi;

(b) the details of other Government buildings, including the Ministerial Hosues where any alterations/additions have been made since issuance of freeze order; and

(c) whether an Expert Group has already submitted a report suggesting

changes in Bye-laws and Rules to enable orderly development of Lutyen's New Delhi and whether Government have taken any decision regarding this?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPTT. OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) No, Sir. The building under reference is not in contravention of the guidelines in respect of Lutyen's Bungalow Zone issued by the erstwhile Ministry of Urban Development in February, 1988, as institutional buildings are allowed in Lytyen's Bungalow Zone.

(b) The CPWD have informed that they have undertaken about 158 works of additions/alterations in bungalows/flats falling within the Lutyen's Bungalow Zone. These works relate to construction of office blocks, security structures, temporary sheds, toilets, porch, car-sheds, extension/covering of verandahs etc.

(c) The report of a Committee on the issue headed by the Chief Planner, TCPO was examined by DDA who made certain recomendations regarding modification of the existing guidelines. The recommendations of DDA have been considered and it has been decided that the existing guidelines do not require any modification.

Representative from Trade Unions in Expert Committee on Tobacco

1775. SHRI S. AUSTIN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not appointed any trade union leader or worker representative in the Expert Committee on tobacco;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to rectify the same?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) to (c) Yes, Sir. However, in order to provided an opportunity to the representatives of farmers and tobacco growers associations, trade unions and beedi industry associations to express their views on the proposed legislation which *inter-alia* seeks to ban the advertisement of tobacco products and regulate the labelling thereof, and an order has been issued inviting the views of the representatives before the Deputy Director General of Health Services, Government of India who would assimilate the same and bring to the notice of the Government.

Comparative Defence expenditure of Asian region countries

1776. SHRI BHUBANESWAR KALITA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the countries of the Asian region, India is spending on defence the lowest proportion of its national resources;

(b) if so, the comparative figures for the countries of the region; and

(c) whether Government intend to step up the above proportion in view of Pakistan's plans to acquire more defence equipment from USA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT) (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Defence Expenditure as a percentage of Gross Domestic Product (GDP), as per published